



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1483]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्येष्ठ 2, 1939

No. 1483]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

का.आ. 1675(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1455(अ) के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अधिकारक्षेत्र अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा;

और जबकि, श्री अनुज कुमार संगल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 10 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1863(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 10 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1863(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्रीमती शदाब बानो, 7वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उक्त विशेष न्यायालय की पीठासीन न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

S.O. 1675(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 1455(E), dated the 25th June, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the District and Sessions Court, Dehradun as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Uttarakhand for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Anuj Kumar Sangal, 2nd Additional District and Sessions Judge, Dehradun who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1863(E), dated the 10th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1863(E), dated the 10th July, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, hereby appoints Smt. Shadab Bano, 7th Additional District and Sessions Judge, Dehradun, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.